:सामन्तवाद:

वर्णसंकर के कारण सामाजिक संकट जन्म लेता है और यह संकट तब उत्पन्न हुआ जब शूद्रों एवं वेश्याओं में सम्बन्ध स्थापित हुये वैश्यों का जो दायित्व था वह था उत्पादन और विपणन वह धन का उत्पादक था और वह कर भी देता था जबकि शूद्रों का कार्य था समाज की सेवा करना अब चूँकि वैश्य और शूद्रों में विवाह सम्बन्ध स्थापित हुये तो इससे इनकी सन्तुष्टि का ह्रास होता है और तब संभवतः दोनों वर्ग अपने कार्यों से विमुख हो जाते हैं ऐसा करके दोनों वर्गों ने ब्राह्मण व क्षत्रिय वर्ग को चुनौती दे दी शासक वर्ग इन दोनों के कर्मों पर आश्रित था।

सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों को भूमिदान दिये और उन्हें दायित्व सौंपा गया कि वे वर्णसंकर को रोके आदर्श समाज वर्ण संकर को रोकने के लिये कृत संकल्प हो गया और वर्ण के सदस्य अपने अपने वर्ण का कार्य करें राजा का यह मुख्य दायित्व हो गया भूमि अनुदान करमुक्त था ब्राह्मणों को शासक वर्ग द्वारा भूमि अनुदान के साथ सामन्तवादी व्यवस्था का जन्म हो जाता है एक मध्यम वर्ग जो राजस्व की व्यवस्था करता है राजा के प्रति निष्ठावान रहता है किन्तु वह कर नहीं देता क्योंकि यह भूमिदान करमुक्त था।

सामन्तवाद के अन्य कारक थे ब्राह्मणों को सीमावर्ती जंगलों में भूमिअनुदान दिया गया भूमि अनुदान के माध्यम से राजा अधिकाधिक भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाना चाहता था सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये, शत्रुओं के आक्रमण को रोकने के लिये, इन क्षेत्रों में आबाद करने वाली जनजातियों के व्यवस्थापन के लिये आर्थिक - सांस्कृतिक संचालन के लिये राजा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में भूमि अनुदान दिये आर्थिक संचालन से उत्पादकता में बढ़ोत्तरी होगी।

परिणामतः व्यापार में बढ़ोत्तरी होगी जिससे राज्य का आर्थिक संचार मजबूत होगा। राजा अपनी सत्ता को वैधानिकता प्रदान करने के लिये भी ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करते हैं ताकि वे लोग ऐसी वंशावली तैयार करें जिससे उनके सम्बन्ध सूर्यवंशीय, चन्द्रवंशीय लोगों के साथ स्थापित करने से उन्हें वैधानिकता और वैधता प्राप्त हो जाती है इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जो भूमि अनुदान किया गया उसका परिणाम सामन्तवाद के रूप में परिणत हुआ।

Scanned with CamScanner

ब्रिटिश काल में भू राजस्व नीति का विकास।

क्लाइव ने बंगाल की गर्वनरी संभालने के पश्चात यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली के अन्तर्गत मुगल सम्राट से दीवानी के अधिकार प्राप्त किये एवं निजामत के कार्य मुगलों को एक निश्चित धनराशि के बदले प्रदान किये इस प्रकार कम्पनी की भू राजस्व की शुरूआत द्वैध शासन से ही जुड़ गयी थी अत: क्लाइव ने ही ब्रिटिश भू राजस्व नीति का बंगाल में निर्धारण किया यद्यपि यह प्रत्यक्ष नही था।

हिन्दू मुस्लिम अधिकारी जो आमिल कहलाते थे के माध्यम से वसूली का प्रावधान किया गया और इस वसूली का एक निश्चित अंश पारिश्रमिक के रूप मे प्रदान किया गया। क्लाइव के बाद वेरेलस्ट ने इस नीति को मूलरूप में ही जारी रखा लेकिन इसने सर्वेक्षणों का सुझाव दिया और कर्टियर द्वारा इस सुझाव पर अमल किया गया लेकिन यह व्यवस्था सफल न हो सकी अन्तत: क्लाइव वाली व्यवस्था निरन्तर बनी रही लेकिन 1772 मे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने यह आदेश जारी किया कि कम्पनी भू राजस्व व्यवस्था को सीधे अपने हाथों मे ले ले इस आदेश को क्रियान्वित करने के लिये वॉरेन हेस्टिंग्ज ने पूरे क्षेत्र को छः समविभागों में बाँटा इनमें कई कई जिले थे और प्रत्येक जिले मे एक रेवेन्यू कॉउन्सिल की स्थापना की साथ ही कलकत्ता में सर्वोच्च निकाय के रूप में कलकत्ता में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गयी इन संविभागो में यूरोपीय कलेक्टर नियुक्त किये गये कोष का हस्तान्तरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया गया और 1772 में पंचवर्षीय आधार पर इजारेदारी व्यवस्था स्थापित की गयी और इसमें जमीदारो को कोई महत्त्व नही दि गयी इस व्यवस्था में 1773 में थोड़ा परिवर्तन करते हुये भ्रष्ट कलेक्टरो का पद मुक्त कर दिया।

वॉरेन हेस्टिंग्स ने भूमि के वास्तविक मूल्य निर्धारण के लिये 1776 में अमीनी आयोग का गठन किया इसी वर्ष एक वर्षीय इजारेदारी व्यवस्था लागू की गयी 1781 में कलेक्टरों को पुनः नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग्स के काल मे कोई स्पष्ट भू राजस्व नीति तैयार नही हो सकी यद्यपि फिलिप फ्रांसिस द्वारा 1776 मे ही जमीदारों के साथ स्थायी बन्दोबस्त का विचार प्रस्तुत किया गया था। अतः ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 1784 के पिट के एक्ट द्वारा कॉर्नवालिस

Scanned with CamScanner

को ब्रिटिश आदेश कि वह भारत में एक स्पष्ट लिखित भू राजस्व नीति तैयार करें के साथ भारत भेजने का प्रावधान किया गया।

कॉर्नवालिस ने जमींदारी बन्दोबस्त पर जॉन शोर एवं जेम्स ग्रांट के साथ मिलकर काम करना था जॉन शोर जमींदार को जमीन का स्वामी मानता था जबकि जेम्स ग्रांट जमींदार को नही बल्कि सरकार को जमीन का स्वामी स्वीकार करता था। बन्दोबस्त के स्वरूप के विषय में अब जॉन शोर की विजय हुयी जिसे 'शोर मन्तूर' कहा गया और यही मन्तूर जमींदारी बन्दोबस्त 1790 का आधार बना।

स्थायी बन्दोबस्त :- स्थायी बन्दोबस्त लागू करते समय इस बात पर विवाद हुआ कि बन्दोबस्त कितने वर्षों के लिये किया जाये प्रारम्भ में यह 10 वर्षों के लिये लागू किया गया था लेकिन बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल द्वारा स्थायी बन्दोबस्त को स्वीकार किया गया और यही बात अपने आप में कुछ विशेषतायें सम्मिलित किये हुये था जिन तत्वों एवं वर्गों के साथ वह बन्दोबस्त किया गया था।

जमींदारी शब्द के अन्तर्गत इन्हे एक जातिगत स्वरूप प्रदान किया गया और जमींदारों को भूमि पर स्वामित्व का अधिकार दिया गया इस बन्दोबस्त का आधार समय पर भू राजस्व की अदायगी था इसके अन्तर्गत कुल भू राजस्व का 10/11 भाग सरकार को 1/11 भाग जमींदार को मिलना था।

यह व्यवस्था प्रथम चरण में बंगाल, बिहार क्षेत्र में लागू की गयी थी और बाद में उड़ीसा, U.P. के बनारस क्षेत्र एवं कर्नाटक के उन जिलों में इसको लागू गया था इस व्यवस्था में भूमि के स्वामित्व को हस्तान्तरण नीलामी द्वारा किया जा सके यदि वह उस समय भू राजस्व अदा न कर सके यद्यपि 1799 एवं 1812 के अधिनियमों से जमींदारों के अधिकारों में वृद्धि की गयी अब उन्हे बिना न्यायालयों की अनुमति के कृषकों की सम्पत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया यद्यपि इन प्रावधानों की आलोचना बाद के दिनों में व्यापक रूप में हुयी थी स्थायी बन्दोबस्त साथ ही कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रखता था इसके अन्तर्गत भू राजस्व दरों का स्थायी रूप होने के कारण इससे भविष्य में सरकारों को अतिरिक्त लाभ की गुंजाइश नही बची थी उत्पादन वृद्धि की स्थिति में भी सरकार को कोई अतिरिक्त लाभ नही था इसमें भूमि के फसल वृद्धि की भी सराहना नही की गयी थी इससे भी सरकार को हानि इंगित होती है।

उपरोक्त सभी नकारात्मक प्रभावों के साथ ही इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण दोष कृषकों का अत्यधिक शोषण था क्योंकि अब कृषक प्रत्यतः जमींदारों के अधीन हो गये थे इस व्यवस्था के माध्यम से अंग्रेजो को सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ यह रहा कि उन्हे भारत में एक वफादार वर्ग का सहयोग प्राप्त हो गया था जो संकट के समय में मध्यमवर्ती वर्ग के तौर पर अंग्रेजो के लिये लाभकारी हो सकता था और ऐसा 1857 के विद्रोह के समय देखने को भी मिलता है।

→ **रैय्यतवाडी व्यवस्था** :→ द० भारत में भू राजस्व व्यवस्था को लाये जाने की आवश्यकता की पूर्ति रैय्यतवाडी व्यवस्था के माध्यम से की गयी अंग्रेजो ने मैसूर के साथ 1792 की श्रीरंगपट्टनम की सन्धि से प्राप्त एक क्षेत्र बारह महल में रैय्यतवाडी महल व्यवस्था का प्रथम प्रयोग कर्नल रीड के द्वारा किया गया तथा 1807 में अर्काट एवं नल्लौर आदि क्षेत्रो में पुन: इसका प्रयोग किया गया लेकिन 1820 में इसे औपचारिक रूप से मुनरो द्वारा मद्रास में दिया गया 1825 में बम्बई एवं 1847 में बम्बई प्रेजीडेन्सी ने भविष्य में इसके विकास की एक रूपरेखा तैयार की।

रैय्यतवाडी व्यवस्था के अन्तर्गत किसानो के साथ सीधा बन्दोबस्त किया गया अर्थात अब कृषक एवं सरकार के मध्य कोई मध्यस्थ नही रहा और यह व्यवस्था भी स्थायी नही थी इसकी दरो में परिवर्तन का प्रावधान था इस व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि सर्वेक्षण के सिद्धान्त को लाया गया इसके अन्तर्गत भूमि का विभिन्न प्रकारो में वर्गीकरण किया जाता था यथा सिंचित भूमि, पथरीली भूमि, शुष्क भूमि ताकि भूमि उर्वरता के आधार पर दरे निश्चित की जा सके।

यह व्यवस्था अपने आप में कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रखती थी क्योकि भू राजस्व दर आमतौर पर ऊँचे स्तर पर रखी जाती थी और भूमि के सर्वेक्षण व माप के सिद्धान्तो को अनदेखा कर बाद के दिनो में निरंकुशशाही तरीको से पिछले रिकॉर्डो के आधार पर भू राजस्व का यह निर्धारण किया जाने लगा सरकार ने यह अधिकार भी अपने पास सुरक्षित रखा था कि वह राजस्व की दरो को कभी भी बढ़ा सकती है अत: यहां शोषणकर्ता के रूप में राज्य स्वयं प्रतीक के रूप में उभरा था साथ ही भू राजस्व अधिक होने से भूमि अर्थव्यवस्था प्रभावित हुयी और इससे उपज में गिरावट इंगित हुयी।

→ **माहलवाडी व्यवस्था** → माहलवाडी व्यवस्था की शुरुआत 1801 में अवध से हुयी 1803 में मराठा विजित क्षेत्र कोंकण में भी इसी को लागू किया गया था 1822 में उ० प० क्षेत्र पंजाब आदि में औपचारिक रूप से मैकेन्जी योजना के अन्तर्गत इसको लागू किया गया था तथा 1833 में थॉमस प्लान के अन्तर्गत संशोधित रूप में महालवाडी व्यवस्था को लाया गया था गाँव के समूह जिसे महाल नाम दिया गया था, के साथ यह व्यवस्था लागू की गयी थी।

माहलवाडी व्यवस्था के द्वारा एक संयुक्त सामूहिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता था इसे व्यवस्था के अन्तर्गत निश्चित अवधि का निर्धारण किया गया और इसमें स्वामित्व का कोई अधिकार नही दिया गया था गाँव के मुखिया को भू राजस्व का उत्तरदायित्व सौंपा गया इसमें दर का निर्धारण प्रारम्भ में 2/3 भाग व बाद में विलियम बैंटिक के द्वारा कम करके 60% कर दिया गया था यद्यपि कुछ क्षेत्रो में यह 50% की दर से भी लागू की गयी थी इस व्यवस्था में सबसे बड़ा दोष यह उत्पन्न हो गया था कि बाद के दिनो में जो सामूहिक इकाई का नेतृत्व करते थे वे अब शक्तिशाली होकर जमींदार के रूप में उभरने लगे थे साथ ही इस व्यवस्था के अन्तर्गत कर की सीमा भी बहुत ऊँची थी इसने सामूहिक रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था और अब जिन क्षेत्रो में भू राजस्व अपेक्षाकृत अधिक ऊँचा था वहां साहूकारो का नियन्त्रण बढ़ने लगा था जिसने धीरे धीरे भूमि पर साहूकारो का नियन्त्रण स्थापित कर दिया था।

Scanned with CamScanner

→ औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के अन्तर्गत परम्परागत शिल्पी उद्योगों का पतन।

→ परम्परागत उद्योगों का पतन भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से सम्बद्ध था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की स्थापना से आये महत्वपूर्ण परिवर्तनों ने परम्परागत उद्योगों के पतन की स्थिति के लिये उत्तरदायी कारकों के रूप में कार्य किया और यह कारक औपनिवेशिक नीतियों में ही अन्तर्निहित थे।

ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद भारतीय राजा रजवाड़ों का पतन हो गया था इससे विशेष प्रकार के उत्पादों की आवश्यकता एवं मांग का भी पतन हो गया चूँकि राजा रजवाड़े इन परंपरागत उद्योगों के संरक्षणदाता थे और इनसे निर्मित उत्पादों की खपत भी इनके द्वारा पूर्ण कर ली जाती थी लेकिन इनके पतन ने इन उद्योगों के बाजार को खत्म कर दिया था साथ ही ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की स्थापना ने मांगों की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाये इनके अन्तर्गत नये व यूरोपीय मांगों या आदर्शों या मांगों को पूरा करने में भारतीय परंपरागत उद्योग असफल रहे इसलिये भी यूरोपीय की तुलना में यह बाजार की दौड़ से बाहर हो गये अतः भारतीय दस्तकारी परम्परा एवं परंपरागत उद्योगों के इस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने से श्रेणियों एवम् अन्य व्यापार संघों जैसे संगठनों का पतन हो गया।

ब्रिटिश व्यापार नीति ने भी भारतीय औद्योगिक उत्पादों की मांगों को प्रभावित किया ब्रिटेन द्वारा भारत में, ब्रिटेन में मशीनों द्वारा बनायी गयी वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन दिया ब्रिटेन ने औपनिवेशिक नीतियों के तहत अपनी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत भारत को कच्चा माल उत्पादक देश के रूप में विकसित कर इस कच्चे उत्पाद को ब्रिटेन की मशीनों द्वारा तैयार माल कर इन्हें भारत में लाकर यहां के परंपरागत उद्योगों के मुकाबले कम मूल्य पर बाजार में उतार दिया गया। इस नीति ने भारतीय परंपरागत उद्योगों को बाजार में मूल्य लागत के आधार पर टिकने नहीं दिया 1813 में ही एक पक्षीय मुक्त व्यापार ने सूती वस्त्र क्षेत्र में इसका प्रोत्साहन प्रमुख रूप से दिया गया और ब्रिटेन द्वारा आयात किये गये उत्पादों पर उच्च स्तरीय प्रशुल्क व्यवस्था लायी गयी ताकि भारतीय उत्पाद वहां के बाजार में अपनी पैठ न जमा पायें।

EIC द्वारा बंगाल के दस्तकारों का शोषण किया गया उसे बाजार दर से कम दर पर सेवा प्राप्त की जाती थी उनसे बाजार दर से कम दर पर ही वस्तुयें भी खरीदी जाती थी इस प्रकार की व्यवस्था से बंगाल की परंपरागत दस्तकारी प्रथा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा साथ ही यहां के कृषक वर्ग का भी शोषण किसी विशेष किस्म की उपज उत्पादित करने के लिये किया जाता था इसके अतिरिक्त इस प्रकार के उद्योगों के पतन में रेलवे आदि की भी भूमिका रही थी अतः व्यवसायिक औद्योगिक, वाणिज्यिक केन्द्रों का इन परिस्थितियों के अन्तर्गत पतन हो गया क्योंकि उद्योगों के पतन ने इन केन्द्रों की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया इस प्रकार केन्द्रों के रूप में सूरत, ढाका, मुर्शिदाबाद आदि का पतन हो गया एवम् साथ ही उत्पादित क्षेत्रों का जैसे गुजरात का कपास क्षेत्र, बंगाल का जूट क्षेत्र आदि के पतन के मार्ग भी प्रशस्त हो गये।

Scanned with CamScanner

परम्परागत उद्योगों के पतन से जो कार्य प्रभावित हुआ अभाव उत्पन्न हुआ व्यापी शर्तें उद्योगों के विकास से नहीं हो पायी थी दस्तकारी एवं श्रमिक वर्ग का भी पतन हुआ और अब वह धीरे धीरे कृषि कार्यों से जुड़ना आरम्भ हुऐ जिसने कृषि पर अतिरिक्त दबाव के रूप में कार्य किया अब उत्पादित क्षेत्रों के पतन के कारण अर्थव्यवस्था में एक आर्थिक खोखलापन उत्पन्न हुआ जिससे भारत में गरीबी एवं निर्धनता को उस काल में इन उद्योगों के पतन से जोड़ा गया।

परम्परागत उद्योगों के पतन के साथ कई सकारात्मक पहलू भी जुड़े थे एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के विकास के लिये इन उद्योगों का पतन एक कारक के रूप में था भारत में अब एक औद्योगिक बाजार का विकास हुआ इससे बाजार से "दबी बिकी वस्तुओं की उपलब्धता को बल मिला भारत का एक विस्तृत औद्योगिकीकरण बाजार के रूप में व्यवस्थीकरण हुआ जिससे विनिमय प्रणाली के आधुनिक स्वरूप का विकास हुआ इस प्रकार का विकास केवल भोग विलास की वस्तुएं एवम् दैनिक आवश्यकताओं तक ही सीमित नहीं था बल्कि यह दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ा था।

इस प्रकार परंपरागत उद्योगों का पतन पूर्व पूँजीवादी, हस्तशिल्प उद्योगों आदि के पतन को बताता है एक अर्थ में सामन्ती आदर्शों व मूल्यों से प्रभावित उद्योगों के पतन को बताता है इससे मजदूर वर्ग का उदय हुआ जो ऐतिहासिक गतिशीलता को इंगित करता है इस वर्ग की बाद के काल में सामाजिक, आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी जो कि आधुनिक उद्योगवाद का परिणाम थी।

Scanned with CamScanner

→ आधुनिक उद्योगों का विकास।

→ 1860 के दशक से आधुनिक उद्योगों के विकास की प्रक्रिया की शुरुआत हुयी यह शुरुआत मुख्यत: ब्रिटिश पूँजी पर आधारित थी और प्रक्रिया मुख्यतः कपास एवं जूट मील आदि से सम्बद्ध थी इसमें भारत की पूँजी का महत्वपूर्ण योगदान नही था और यह एक धीमी प्रक्रिया थी ब्रिटिश पूंजी का निवेश यद्यपि इसलिये नही किया गया था कि भारत का औद्योगिकरण किया जाये बल्कि इसका भारत में निवेश का उद्देश्य औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के अन्तर्गत भारत का संगठित रूप से आर्थिक शोषण करना था।

स्वदेशी आन्दोलन से स्वदेशी उद्योगों के विकास को प्रेरणा मिली क्योंकि इस आन्दोलन ने जनचेतना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था इसके अन्तर्गत नये प्रकार के उद्योगों की स्थापना हुयी इन उद्योगों में भारतीय पूँजी ~~ने~~ महत्वपूर्ण योगदान दिया था इसके द्वारा जूट, कपास मीलों एवं बैंको आदि की संख्या में वृद्धि हुयी और प्रथम विश्व युद्ध के काल में पुन: भारत में उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिला क्योंकि इस काल में यूरोप से भारत में होने वाले निर्यात व्यापार का पतन हो रहा था इससे भारतीय बाजार में नवगठित भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का अधिक सामना नही करना पड़ा और अब भारतीय वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि होने लगी थी जिसका आधार पहले ही स्वदेशी आन्दोलन ने तैयार कर दिया था।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ ~~विशेष प्रकार~~ ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन मिला या देने की नीति का अनुसरण किया गया जिसके अन्तर्गत 1922-23 में विभेदकारी संरक्षण की नीति को प्रोत्साहन दिया गया लेकिन पुन: द्वितीय विश्व युद्ध में वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी जैसी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान थी अर्थात इस समय उन्हें भारतीय उद्योगों के लिये अनुकूल परिस्थितियों का विकास हुआ इसने आधुनिक उद्योगों के विकास को और अधिक बल प्रदान किया। इसके पश्चात जब देश आजाद हुआ तो भारत ने पहली औद्योगिक नीति 1948 के द्वारा उद्योगों के विकास के लिए एक क्रमबद्ध नीति का क्रियान्वयन किया।

आधुनिक उद्योगों के विकास का स्वरूप धीमा और असमान विकास को इंगित करता है जो कि कुछ खास क्षेत्रों में विकास की प्रादेशिक असन्तुलन की नीति और संकेत देता है क्योंकि इस समय केवल विशेष प्रकार के उद्योगों का ही यथा कपास, जूट, चीनी का ही विकास दिखायी देता है जबकि पूँजीगत वस्तु उद्योग के विकास की गम्भीर सीमायें तथा बुनियादी उद्योगों का बहुत सीमाओं तक अनुपस्थित रूप दिखायी देता है इसके अतिरिक्त तकनीकी विकास की गंभीर सीमायें विद्यमान थी तथा 1920 के पूर्व तक तो इन उद्योगों में ब्रिटिश पूंजी का ही प्रभुत्व था जो इनके एकाधिकार इंगित करता है।

Scanned with CamScanner

आधुनिक उद्योगों का विकास एक सकारात्मक पहलू भी था इन उद्योगों के विकास से अर्थव्यवस्था में एक नवीन तंत्र का उद्भव हुआ इससे अर्थव्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन आया अब कृषक अर्थव्यवस्था और हस्तशिल्प आधारित अर्थव्यवस्था की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की एक प्रक्रिया आरम्भ हुयी भारतीय अर्थव्यवस्था के एकीकरण को बल मिला एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ साथ ही नगरीकरण की प्रक्रिया को दृढ़ सीमाओं पर बल मिला इससे नये नगरों के उद्भव की पृष्ठभूमि तैयार हुयी जो कि प्रजातान्त्रिक जीवन, धर्म निरपेक्ष जीवन और प्रगतिशील केन्द्र के आन्दोलन के रूप में उभरी नवीन सामाजिक वर्गों का उद्भव हुआ इसके अन्तर्गत पूँजीवादी वर्ग एवं संरचना और सामाजिक सम्बन्धों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आये जिसने राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया और आधुनिक उद्योगों का विकास राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्य धारा से जुड़ गया।

→ ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तहत भारत में आर्थिक नीतियां।

→ भारत में ब्रिटिशकालीन आर्थिक नीतियों इनके सम्पूर्ण शासनकाल में एक समान स्वरूप ~~अक्स~~ ग्रहण नहीं करती है बल्कि वो अलग अलग कालों में अलग अलग रूपों को ग्रहण करती है प्रारंभिक चरण में (1757-1813) जो कि 1757 में प्लासी के युद्ध की जीत के साथ प्रारम्भ हो जाता है इसमें अंग्रेजों का एकाधिकार, व्यापार एवं प्रत्यक्ष लूट का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है इस दौरान अंग्रेजों ने व्यापारिक व वाणिज्यिक हितों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया।

अपने हितों को सुरक्षित रखने के अन्तर्गत इन्होंने कई उपाय किये यथा भारत में उपस्थित यूरोपीय विपक्ष की समाप्ति, व्यापार वाणिज्य की सुरक्षा के सभी अवरोधों को समाप्त करना, अपने क्षेत्र की सुरक्षा के तहत पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को सुरक्षित रखवाना तथा इन प्रयासों के अन्तर्गत ब्रिटिश आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रति संतुलित करना था अंग्रेजों ने भारतीय क्षेत्रों पर राजनीतिक नियन्त्रण की स्थापना द्वारा प्रत्यक्ष लूट के आधार को तैयार किया जो बंगाल एवं द० भारत में राजनीतिक नियंत्रण की स्थापना में विशेष महत्व रखता है प्रत्यक्ष लूट के अन्तर्गत धन का निर्गमन जो प्लासी युद्ध के पश्चात शुरू हुआ और जिसका संगठित स्वरूप बक्सर युद्ध से शुरू हुआ, इसमें विशेष महत्व रखता है कम्पनी सरकार द्वारा इस काल में व्यापक स्तर पर भारतीय मौलिक व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया बस यह परिवर्तन मुख्य राजस्व एवं सैन्य व्यवस्था से जुड़ा था।

औपनिवेशिक आर्थिक नीति का दूसरा चरण 1813 से 1860 ई० में औद्योगिक क्रान्ति से उद्योगपतियों के एक नये समूह का जन्म हुआ इस नये समूह का कम्पनी के एकाधिकार व्यापार के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण था इस समूह ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव समूह के रूप में कार्य किया इस प्रकार के दबाव का परिणाम ~~1813~~ 1813 के चार्टर एक्ट के रूप में सामने आया अब मुक्त व्यापार की इस प्रक्रिया द्वारा भारतीय अर्थ-व्यवस्था ब्रिटिश पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ साथ विश्व पूँजीवादी व्यवस्था के साथ एकीकृत हो गयी। नवीन औपनिवेशिक व्यवस्था ने नवीन राजनीतिक प्रशासनिक दृष्टिकोण को जन्म दिया जिसका उद्दे० बाजार के उद्दे० की पूर्ति से जुड़ा था इसने व्यापारिक स्वरूप में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये क्योंकि भारतीय समाज के वैधानिक ढाँचे को पूँजीवादी एवं वाणिज्यिक

Scanned with CamScanner

ढाँचे के अन्तर्गत विकसित करने की प्रबल आवश्यकता थी अर्थात इस समय एक उदारवादी, साम्राज्यवादी, राजनैतिक विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। ताकि भारतीयों के रूढ़िगत विचारधारा को समाप्त कर उसे ब्रिटिश माल का उपभोक्ता वर्ग के रूप परिवर्तित किया जा सके।

आर्थिक नीतियों का तृतीय चरण 1860-1947 तक के काल के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है इस काल में निजी पूँजी निवेश को प्रोत्साहन देने की नीति अपनायी गयी अर्थात अब शोषण का आधार निवेश हुआ तैयार हुआ पूँजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा रेलवे में निवेश और भारतीय ब्रिटिश सरकार को ऋण देने से जुड़ा था और इसका बहुत छोटा सा हिस्सा चाय, जूट, कोयला खनन एवं बैंकिंग व्यापार से जुड़ा था इसके अतिरिक्त निवेश पूँजी को सुरक्षित रखना इस दृष्टिकोण का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू था इस काल में आधुनिकता के विकास की प्रक्रिया को रोकने का प्रयास किया गया इसके अन्तर्गत आधुनिक एवं प्रगतिशील विचारों के प्रसार एवं विकास को प्रोत्साहन नहीं दिया गया।

अतः इस काल में औपनिवेशिक शोषण की इस प्रक्रिया ने अंग्रेजों आर्थिक नियन्त्रण को सुदृढ़ता प्रदान की जिसने अन्ततः ब्रिटिश औपनिवेशिक नियन्त्रण को ही बल प्रदान किया और भारत के आर्थिक शोषण को बढ़ावा दिया।

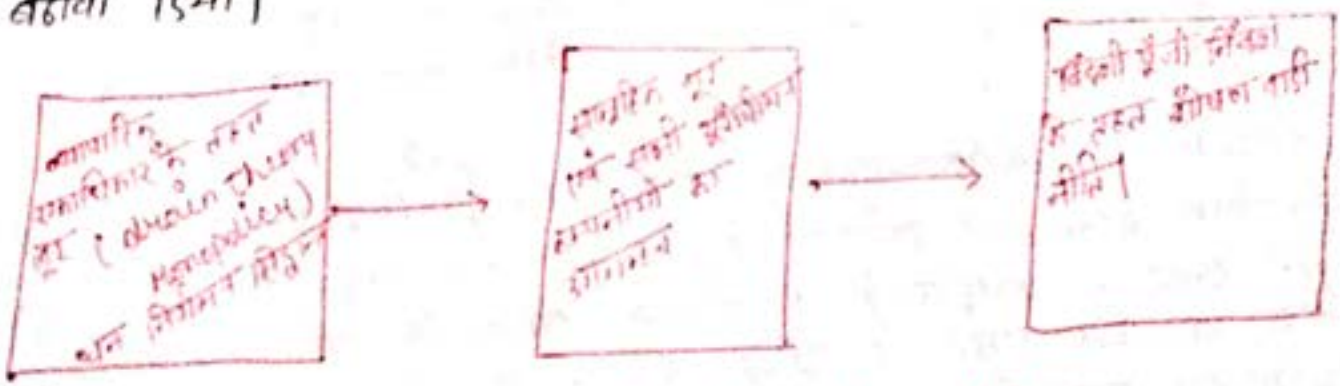

'कम्पनी की आर्थिक नीति'

Scanned with CamScanner

→ ब्रिटिश आर्थिक नीति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन

→ ब्रिटिश आर्थिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी व दरिद्रीकरण को प्रोत्साहन दिया क्योंकि ब्रिटिश भारतीय जनता के हितों के प्रति सजग नहीं थे बल्कि वे उपयोगितावादी विचारधारा के अन्तर्गत ब्रिटिश समाज के विकास के लिये कार्य कर रहे थे इसी क्रम में इन्होंने ऐसी आर्थिक नीतियों को क्रियान्वित किया जिससे ब्रिटिश समाज का आर्थिक उत्थान हो चाहे यह उत्थान भारतीयों की कीमत पर ही क्यों ना हो इसके लिये इन्होंने एकाधिक नीतियों का क्रियान्वयन किया जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को कई रूपों में प्रभावित किया।

→ ब्रिटिश भू राजस्व नीति → ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात भू राजस्व की दर अधिकतम बिन्दु स्तर पर निर्धारित की इससे अधिशेष उत्पादन किसानों के पास नहीं रहा परिणामतः उनकी क्रय क्षमता में ह्रास हुआ और उनका जीवन यापन अत्यधिक कठिन हो गया और उनके पास कृषि में अधिशेष निवेश के लिये धन न बचा जबकि शासक वर्ग ने कृषि में अपनी रूचि न दिखायी इससे कृषि पिछड़ती चली गयी इस अतिरिक्त राशी के लिये कृषक महाजनों के चंगुल में फँसते चले गये और परिणामतः वे भुखमरी आदि के शिकार होते चले गये।

→ भूमि को विक्रय योग्य बनाया जाना → ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अब भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देकर इसे विक्रय की वस्तु बना दिया अब यदि कोई कृषक समय पर भू राजस्व न चुका कर सके तो इसे चुकता करने के लिये महाजनों के चंगुल में फंसता चला गया और अब उसे अपनी भूमि विक्रय करने का ही रास्ता बचा परिणामतः धनी और धनी एवं गरीब और गरीब होते चले गये जिसने किसानों के बीच स्तर भेद को बढ़ावा दिया इसके अतिरिक्त ऊँचे स्तर पर निर्धारित किया गया भू राजस्व की राशी चुकता करने के लिये किसान नगदी फसलों के उत्पादन की ओर उन्मुख हुये परिणामस्वरूप कृषि के व्यवसायीकरण को प्रोत्साहन मिला परन्तु कृषि के व्यवसायीकरण का लाभ मध्यस्वत्व बिचौलियों, महाजन और व्यापारियों को प्राप्त हुआ सामान्य कृषक इससे लाभान्वित नहीं हुये बल्कि इससे गरीबी-भुखमरी को ही प्रोत्साहन मिला।

Scanned with CamScanner

→ कम्पनी सरकार का आयात विशेष वस्तु पर केन्द्रित :- ब्रिटिश कम्पनी व अगे ब्रिटिश सरकार का मुख्य बल उत्तर भारत से विशेष कर अनाजों के निर्यात पर भी रहा चूँकि ब्रिटेन में कृषि योग्य भूमि का अभाव था और वहां औद्योगिकरण के तहत नगदी फसलें उत्पादित की जा रही थी इसलिये भारत से अतिरिक्त अनाजो का निर्यात किया जाता रहा इससे भारत में अतिशेष अनाजो का अभाव होता चला गया परिणामतः किसी आपदा के समय किसान अतिशेष अनाजों के अभाव के कारण भुखमरी की कगार पर आ गये साथ ही ब्रिटिश व्यापार नीति ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को भी हतोत्साहित किया इसी के तहत 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश वस्तुओं का दरवाजा भारत में सभी के लिये खोल दिया गया परिणामस्वरूप वस्तुओं के प्रतिस्पर्धा की अवस्था में भारतीय कुटीर उद्योग प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने लगे जिससे कृषि पर जनसंख्या का अतिभार बढ़ने लगा और कृषि में अतिशेष निवेश न होने के कारण कृषि अर्थ भी पिछड़ती चली गयी जिसने समाज बेरोजगारी को और भी प्रोत्साहन दिया।

→ भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की पूँजीवादी अर्थव्यवस्था से जोड़ना :- ब्रिटिश सरकार ने अपनी आर्थिक औपनिवेशिक नीतियों के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था का एकीकरण कर उसे विश्व पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ जबरन जोड़ दिया परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन में भारत की स्थिति बहुत निम्न हो गयी वह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत कच्चे मालों का निर्यातक बना रहा क्योंकि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का ढाँचा ब्रिटेन में होने वाले औद्योगिकरण के लिये किया जाता रहा इससे भारत विश्व बाजार के साथ साथ अपने घरेलू बाजार में भी भूरीणीमन मालो से पिछड़ने लगा और उसके उद्योग बंद होने लगे सबसे बढ़कर भारतीय हस्तशिल्प उद्योगो के विनाश की क्षतिपूर्ति आधुनिक उद्योगो की स्थापना के द्वारा नही की गयी बल्कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत में केवल उन्ही उद्योगो की स्थापना बल दिया गया जो उद्योग

Scanned with CamScanner

उनके औपनिवेशिक हितों के अनुकूल थे। अतः ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों में भारत में रेलवे यातायात, संचार व्यवस्था, बैंकिंग संस्थायें आदि स्थापित किये गये लेकिन इनका स्वाभाविक परिणाम था कि जहां एक तरफ भारत का ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ गया लेकिन वहीं स्थानीय क्षेत्र विकसित होने लगा इस प्रकार

इस प्रकार स्वतन्त्रता से पूर्व ही भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रकार की विकलांगता आ गयी थी जिसका कुछ रूप आज तक विद्यमान है इस विकलांगता ने भारत को दरिद्रीकरण के स्तर पर पहुंचा दिया था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जिस समय इंग्लैण्ड में आर्थिक सम्पन्नता विकसित हो रही थी उस समय भारत को दरिद्र करके ब्रिटिश समाज को सम्पन्न किया जा रहा था जिसने भारत के प्रत्येक वर्ग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था जो कि औपनिवेशिक सत्ता के स्वरूप में ही निहित होता है।